प्रादेशिक समाचार बुलेटिन,
आकाशवाणी, लखनऊ।

प्रसारण तिथि : 23.07.2024 प्रसारण समय : 19:20 बजे

मुख्य समाचार :–

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट किया पेश : नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती पचास हजार रुपये से बढाकर 75 हजार रुपये हुई।
2. बजट में चार करोड से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढाने की पांच योजनाओं के लिये दो लाख करोड रुपये के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा।
3. विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कम्पनियों पर कॉरपोरेट कर दर चालीस प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई।
4. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा– 140 करोड़ लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है बजट। और
5. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से किया इनकार : कहा– मौजूद आंकड़े नीट पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने के नहीं देते संकेत।

———————

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024–25 का आम बजट पेश किया। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है।

श्रीमति सीतारामण ने आज सातवीं बार बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं कीं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन भोगियों क लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। तीन लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपए तक की आय पर पांच प्रतिशत, सात लाख से दस लाख रुपए तक दस प्रतिशत, दस से बारह लाख रुपए तक पंद्रह प्रतिशत, बारह से पंद्राह लाख रुपए तक बीस प्रतिशत और पंद्राह लाख रुपए से अधिक आय पर तीस प्रतिशत तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17 हजार पांच सौ रुपए तक की बचत हो सकेगी।

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है। हमने पिछले पाँच वर्षों में अनेक उपाय किए हैं, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं

प्रारम्भ करना शामिल है। वित्तवर्ष 2022–23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ।

बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एम एस एम ई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में एक महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केनद्रित होगी। वित्तमंत्री ने बताया कि कृषि और सबंधित क्षेत्रों के लिए एक लाख 52 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के वास्ते विदेशी कम्पनियों पर कॉरपोरेट कर दर चालीस प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। अगले दो वर्ष में पूरे देश में

एक करोड किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण–पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। दस हजार आवश्यकता आधारित संसाधन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार एक करोड शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए दस लाख करोड रुपये का निवेश करेगी।

————————

बजट पेश होन के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि यह बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बाइट.....

ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि के राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नये अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी।

————————

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी और देश के 140 करोड़ लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है। आम बजट 2024–25 विकसित

भारत–आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। बाइट.....

आम बजट सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी विकासोन्मुख एक सौ चालीस करोड़ भारतवासियों की आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट दो हजार चौबीस पच्चीस आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंतोदय की पावन भावना विकास की असीम संभावना है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए एक लाख बावन हजार करोड़ रुपए कृषि और सहायक सेक्टर के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है।

————————

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

जिंगल

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है।

————————

केन्द्रीय बजट की अलग–अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने प्रशंसा की है। लखनऊ के डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. एपी तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक संतुलित बजट है, जिसका लक्ष्य कृषि

उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। बाइट.....

मेरा मानना है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जो सामर्थ्य है उसका सम्यक विकास होगा और यदि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है लगातार तो दो हजार सैंतालीस तक एक विकसित देश के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पर साकार हो सकेगा।

अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बृजेंद्र सिंह ने कहा कि बजट कृषि क्षेत्र और उससे जुड़ी गतिविधियों को और मजबूत करेगा, जिससे ग्रामीण अथव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी।

बाइट.....

बजट जो आज प्रसारित किया गया है यह मुख्य ग्रामीण अंचलों को किसानों को कृषि पर आधारित जितने स्वरोजगार है और कृषि में जो इन्वेस्ट करने के लिए जितने हमारे एमनुस है और हम कैसे ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाए ताकि वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े इन सबके लिए ये बजट बहुत कल्याणकारी है।

————————

कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आय असमानता दूर करने क लिए कुछ नहीं किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने में विफल रहा है।

————————

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े नीट पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने के संकेत नहीं देते हैं। ऐसे में इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 23 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आईआईटी दिल्ली से प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब तय किये जाने के बाद कोर्ट ने विकल्प 4 को सही मानकर दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया।

(समाप्त)